भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1630

उत्तर देने की तारीख : 10.12.2025

तेलंगाना में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की स्थिति और प्रगति

1630. श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य में कार्यान्वित की जा रही सभी प्रमुख योजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है जिनमें छात्रवृत्ति कार्यक्रम, कौशल विकास पहल, महिला सशक्तिकरण योजनाएं तथा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएम-जेवीके) के अंतर्गत अवसंरचनात्मक परियोजनाएं सम्मिलित हैं;

(ख) प्रत्येक योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है, तथा विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं और समर्थित संस्थानों का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तेलंगाना सरकार द्वारा कार्यान्वयन प्रगति, निधि उपयोग और प्रस्तुत लंबित प्रस्तावों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) स्वीकृत परियोजनाओं, चल रहे कार्यों, छात्रवृत्ति वितरण और कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का योजना-वार और जिले-वार ब्यौरा विशेषकर नलगोंडा जिले के लिए क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार के लिए नलगोंडा को अतिरिक्त परियोजनाएं आवंटित करने, सुविधाओं का उन्नयन करने या विशेष सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान तेलंगाना राज्य के संदर्भ में मंत्रालय की मुख्य योजनाओं और उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

पीएमजेवीके:

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) एक केंद्र-प्रायोजित योजना है जो देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, महिला केंद्रित परियोजनाएं, पेयजल एवं आपूर्ति, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय

ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन और अन्य सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना के निर्माण हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

इस योजना के तहत, परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा तैयार की जाती है और उनका निष्पादन, संचालन एवं देखरेख भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। मंत्रालय द्वारा वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति का आकलन करने तथा समय पर उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा बैठकें एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने प्रस्ताव उचित माध्यम से समर्पित पीएमजेवीके ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत करते हैं। पीएमजेवीके दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 से तेलंगाना राज्य की ओर से अपेक्षित उचित माध्यम से कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

पीएम विकास:

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसमें पांच पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'नई रोशनी', 'हमारी धरोहर' और 'उस्ताद' को एकीकृत किया गया है तथा इसका मुख्य उद्देश्य तेलंगाना राज्य सहित पूरे देश में कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं में उद्यमशीलता और नेतृत्व को बढ़ावा देने और स्कूल ड्रॉपआउट छात्रों को शिक्षा सहायता प्रदान करके छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के नाते, विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं, इसलिए मंत्रालय द्वारा लक्ष्य आवंटन का जिला-वार विवरण नहीं रखा जाता है। हालांकि, 2025-26 के दौरान तेलंगाना राज्य में योजना के गैर-पारंपरिक घटक के तहत प्रशिक्षण के लिए विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) को लगभग 3,300 लाभार्थियों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। हालांकि, यह स्वीकार करते हुए कि कुछ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में लक्षित और समग्र व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है, सरकार नलगोंडा जैसे जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए रोजगार बढ़ाने और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ बनाने के लिए देश भर में पीएम विकास लागू कर रही है।

मंत्रालय वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत लक्ष्यों के आवंटन के लिए अपने विशेष पोर्टल, यानी https://pmvikas.minorityaffairs.gov.in/ के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित कर रहा है।

छात्रवृत्ति:

मंत्रालय ने केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू किया है।

i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना;

ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; और

iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना।

हालांकि, छात्रवृत्ति योजनाओं को 2021-22 के बाद लागू करने के लिए मंजूरी नहीं दी गई है।

एनएमडीएफसी:

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) देश भर में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के 'पिछड़े वर्गों' के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महिलाओं और कारीगरों को प्राथमिकता देते हुए स्वरोजगार आय सृजन उद्यमों को रियायती ऋण प्रदान करके अपनी योजनाओं को लागू करता है।

एनएमडीएफसी की योजनाओं को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (SCA), पंजाब ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक और केनरा बैंक के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

2021-22 से 2024-25 तक, एनएमडीएफसी द्वारा केनरा बैंक को पुन: वित्तपोषण के माध्यम से तेलंगाना राज्य के लाभार्थियों को जो सहायता प्रदान की गई है, वह इस प्रकार है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**धनराशि (करोड़ रु. में)**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	2021-22	1.55	169
2	2022-23	6.08	669
3	2023-24	0.22	35
4	2024-25	0.04	8

*****